सम्पादक के नाम

मनमोहन सिंह का यूपीए का कार्यकाल आज के मोदीराज की तुलना में बेहतर नज़र आने लगा है

ऐसा नही है कि यूपीए के शासन काल मे घोटाले नही हुए, हुए ओर तुरंत सामने भी आए, दोषियों पर कार्यवाही भी हुई। आज हो ये रहा है कि घोटाले ₹ से कही ज्यादा हो रहे है ,भ्रष्टाचार इतना है कि सीबीआई का नम्बर 2 अधिकारी अपने बॉस पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रहा है, उसका बॉस अपने अधीनस्थ अधिकारी को सीबीआई के दफ्तर में गिरफ्तार कर रहा है लेकिन यह कोई कहने को तैयार नही है कि यह सब हो रहा है। तब मोदी जी क्या कर रहे है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नही बनती है ?

कल एक खबर ओर भी आई केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को 2014 से 2017 के बीच केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का खुलासा करने का निर्देश दिया है। यानी कि मोदी जी का यह कहना बिल्कुल झूठा था कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार ही नही हुआ, भ्रष्टाचार तो हुआ पर उसे सामने ही नही आने दिया गया।

मुख्य सूचना आयुक्त ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की अर्जी पर यह फैसला सुनाया है अपने आरटीआई आवेदन में संजीव चतुर्वेदी ने भाजपा सरकार की 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया', 'स्वच्छ भारत' और 'स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट' जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में भी सूचनाएं मांगी थी। पीएमओ से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर चतुर्वेदी ने आरटीआई मामलों पर सर्वोच्च अपीलीय निकाय केंद्रीय सूचना आयोग में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान चतुर्वेदी ने आयोग से कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ प्रधानमंत्री को सौंपी गई शिकायतों की सत्यापित प्रतियों के संबंध में विशेष सूचना मांगी है, जो उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को 15 दिन के अंदर विदेशों से वापस लाए गए काले धन की जानकारी देने को भी कहा है।

लेकिन इस आदेश से कुछ होने जाना वाला नही है इससे पहले क्योंकि कुछ समय पहले मुख्य सूचना आयुक्त ने पीएमओ को निर्देश दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम प्रकट किए जाने चाहिए। CVC ने नामों को प्रकट करने में पीएमओ द्वारा ''राष्ट्रीय सुरक्षा'' के आधार पर जताई गई आपत्ति को खारिज कर दिया था, लेकिन इस आदेश को भी हवा में उड़ा दिया गया।

दरअसल मोदी सरकार की कड़ी आलोचना इस बात के लिए की जानी चाहिए कि उसने आरटीआई कानून को बिल्कुल पंगु बना दिया, देश में RTI के दो लाख से अधिक मामले लटके हुए हैं। आरटीआई लगाने पर न तो जानकारी मिल रही है न दोषी अधिकारियों पर पेनल्टी होती है। केंद्रीय सूचना आयोग में आयुक्तों के 11 में से 4 पद खाली पड़े हैं ष्टुङ्कष्ट आदेश भी जारी कर दे तो कोई सुनता नही है।

आरटीआई कानून की उपेक्षा करना मोदी सरकार के सबसे बड़े अपराधों में से एक है।

– गिरीश मालवीय

वित्त मंत्री अरुण जेटली की बेटी मेहुल चोकसी के पेरोल पर थी

राहुल गाँधी ने अपने ट्वीट में ICICI बैंक का एक अकाउंट नंबर सार्वजनिक करते हुए कहा कि 'वित्त मंत्री अरुण जेटली की बेटी मेहुल चोकसी के पेरोल पर थीं, जबकि उनके वित्त मंत्री पिता ने चोकसी की फाइल दबाए रहे और उन्हें देश से भाग जाने दिया. उन्हें मेहुल चोकसी की कंपनी से 24 लाख रुपए मिले. दुख है कि मीडिया ये खबर नहीं दिखा रहा है, लेकिन देश के लोग समझदार हैं. दरअसल आपको याद होगा कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पीएनबी घोटाले के संबंध में एक खबर आयी थी कि देश की सबसे बढ़ी लॉ फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास सीबीआई जांच के दायरे में आ गयी हैं. घोटाले में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है. अधिकारी इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि यह फर्म न तो पीएनबी की तरफ से और न ही नीरव मोदी की तरफ से कोई केस देख रही थी तो ऐसे में इस लॉ फर्म में घोटाले से जुड़े कागजात कैसे और क्यों पहुंचे ?

20 फरवरी को सीबीआई के अधिकारियों ने इस लॉ फर्म में छापेमारी की थी, नीरव मोदी के दफ्तर से ट्रकों में भरकर करीब 50-60 कार्टूनों में पैक कर ये कागजात मंगवाए गए थे. सीबीआई के सूत्र कह रहे हैं संभवत: यह फर्म नीरव मोदी की मदद करना चाह रहा थी. मीडिया से यह कहलवाया जा रहा था कि नीरव मोदी के पक्ष से यह कागजात किसी ने नही भेजे बल्कि लॉ फर्म को यह शौक चर्राया कि वह नीरव मोदी की मदद कर दे.

दरअसल इस खबर को इस तरह से क्यों पेश किया गया उसमें भी एक राज छुपा हुआ है बात यह है कि पीएनबी घोटाला सामने आने के ठीक पहले अरुण जेटली की बेटी और दामाद की लॉ फर्म 'जेटली एंड बख्शी' ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से एक रिटेनरशिप अनुबंध किया था. (रिटेनरशिप किसी कानूनी फर्म/वकील के साथ किया जाने वाला करार है, जिसके तहत किसी आगामी मुकदमे के लिए फर्म/वकील को मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुबंधित कर एडवांस दे दिया जाता हैं). जेटली के दामाद जयेश बक्शी ने इस अनुबंध के तहत पैसा लेना स्वीकार भी किया था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमने पैसा दिसंबर 2017 में लिया और जनवरी 2018 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से वापस भी कर दिया.

यदि दोनों बातें समान है यदि सीरिल अमरचंद मंगलदास की जाँच की जा रही है तो जेटली की बेटी दामाद की लॉ फर्म की जांच क्यो नही की जा रही है. 24 लाख रूपया जो दिया गया है वह आखिरकार अरुण जेटली की बेटी दामाद की फर्म को ही तो दिया गया है तो यह क्यों न माना जाए कि जेटली को भनक थी कि कुछ गड़बडी जरूर है ?

– साइबर नजर

मोदी के भ्रष्टचार विरोधी चेहरे पर कालिख पुती, अब धर्म की गंगा में अपना मुंह धुलेंगे या पंचगव्य खाकर खुद को पवित्र करेंगे ?

सिद्धार्थ रामू

मोदी के भ्रष्टचार विरोधी चेहरे पर भी कालिख पुती, अब धर्म की गंगा में अपना मुंह धुलेंगे या पंचगव्य खाकर खुद को पवित्र करेंगे. ये तो वही जाने या उनके भक्त जाने! मोदी भ्रष्टाचार के खात्में और विकास के नारे आधार पर सत्ता में आए थे। मोदी के विकास का अर्थ अडाणी-अंबानी और नीरव मोदी जैसे लोगों को देश को लूटने की छूट देना है, यह अंधे हिंदू भक्तो को छोड़कर सबको पता चल चुका है। अब भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं।

अपने चहेते अधिकारी राकेश आस्थाना को बचाने के लिए मोदी ने आनन-फानन में सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया और पहले से भ्रष्टाचार के 6 आरोपों में घिरे नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने बुधवार को ही अपना कार्यभार संभाला।

इसी के साथ ही सीबीआई में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। अरुण शर्मा को जेडी पॉलिसी, जेडी एंटी करप्शन हेडक्वार्टर से हटा दिया गया है। AC III के डीआईजी मनीष सिन्हा को भी उनके पद से हटा दिया गया है। इस तरह आलोक वर्मा के नजदीकी 6 अधिकारियों को हटा दिया गया है।

गौरतलब है कि अस्थाना और कई अन्य के खिलाफ कथित रूप से मांस निर्यातक मोइन क़ुरैशी से घूस लेने के आरोप में रविवार को एफआईआर दर्ज की गई है। क़ुरैशी धनशोधन और भ्रष्टाचार के कई मामलों का आरोपी है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2017 और अक्टूबर 2018 के बीच कम से कम पांच बार रिश्वत दी गई। इसके एक दिन बाद डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। मोदी-अमितशाह से राकेश आस्थाना काफी करीबी हैं।

1984 बैच के गुजरात काडर के आईपीएस अफसर सीबीआई के भीतर छिड़े घमासान के केंद्र में हैं। अस्थाना के साथ काम कर चुके एक पूर्व IPS अफसर ने कहा, 'वह कांग्रेस की सोच, गुजरात में पार्टी की सरकार के कामकाज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे।'

गुजरात के उद्योगपतियों से घनिष्ठ रिश्ते

IPS के तौर पर अपने शुरुआती पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान अस्थाना की एक ईमानदार, मेहनती और आसानी से पहुंच वाले अफसर की छवि बनी। अपनी पब्लिक इमेज बेहतर रखते हुए अस्थाना ने गुजरात के बड़े उद्योगपतियों से करीबी बढ़ानी शुरू की। एक अधिकारी ने बताया, 'गुजरात के दूसरे आईपीएस अफसर शराब तस्करों से रिश्वत लेने या फेक एनकाउंटर्स में संकोच नहीं करते थे जबकि अस्थाना ने अपनी नजरें बड़ी मछली पर गड़ाईं।'

मोदी और आडवाणी से रिश्ते

ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और राकेश अस्थाना शुरू से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दरअसल, अस्थाना पहले लालकृष्ण आडवाणी के काफी करीब थे। 90 के दशक के मध्य में अस्थाना ने CBI में प्रतिनियुक्ति मांगी और 1996 में उन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में गिरफ्तार किया गया। बीजेपी के एक वरिष्ठ सांसद ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, 'इसके बाद अस्थाना की छवि एक ऐंटी-कांग्रेस अफसर की बन गई।'

2002 कांड SIT जांच की मिली जिम्मेदारी

2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अस्थाना को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेजडी की जांच के लिए स्क्वॉड को लीड करने के लिए कहा गया। अयोध्या से लौटते समय गोधरा में ट्रेन के S6 कोच में आग लगने से कई कारसेवकों की मौत हो गई थी। वह अस्थाना ही थे, जिन्होंने पहली बार सार्वजनिक बयान देते हुए आग को सोची-समझी साजिश करार दिया था। भीतरखाने के लोगों का कहना है कि स्क्वॉड को हेड करने के लिए अस्थाना की नियुक्ति वास्तव में मोदी की मदद करने का आडवाणी का आइडिया था।

मोदी और आस्थाना के बढते रिश्ते

जैसे-जैसे मोदी का कद बढ़ता गया और वह आडवाणी से दूर होते चले गए, अस्थाना ने भी सीएम से करीबी बढ़ानी शुरू कर दी। अस्थाना के करीबी होने का दावा करने वाले एक उद्योगपति ने हमारे सहयोगी अखबार मिरर को बताया, 'मोदी भक्त बनने के लिए हमने 2002 में अस्थाना को चिढ़ाया था। हालांकि उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया।'

मोदी के समय नहीं मांगी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति

मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद अस्थाना ने कभी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति नहीं मांगी। अमित शाह के करीबी और गुजरात बीजेपी के एक मंत्री ने कहा, 'लोगों की धारणाओं से उलट, अमित शाह और अस्थाना एक दूसरे के संपर्क में आए, जब मोदी CM बने।' उन्होंने आगे कहा, 'अस्थाना और मोदी काफी घनिष्ठ हैं।' नेता ने कहा कि बतौर सीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान अस्थाना को शानदार पोस्टिंग मिलती रही। इसके साथ ही इशरत जहां फेक एनकाउंटर केस हो या आसाराम बापू रेप केस, अस्थाना गुजरात में बीजेपी सरकार के मददगार बनकर उभरे।

इशरत जहां केस में घिरे

इशरत जहां केस में गुजरात काडर के एक और आईपीएस अफसर सतीश वर्मा ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि गुजरात सरकार के प्रभाव में कैसे अस्थाना ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए एक फरेंसिक अधिकारी को मजबूर करने की कोशिश की थी। वर्मा अपनी सॉलिड जांच के लिए जाने जाते थे।

बेटी की शादी के राज्यभर में चर्चे

अस्थाना को 'मैन ऑफ स्टाइल' कहा जाता था। 2016 में वडोदरा में जब उनकी बेटी की शादी हुई, तो पूरे राज्य में इसकी चर्चा हुई। हफ्ते भर चले कार्यक्रम में अस्थाना ने अपने अतिथियों का फाइव-स्टार सत्कार किया। बाद में सबको पता चला कि सभी होटल्स ने अस्थाना और उनके परिवार को मुफ्त सेवाएं दी थी।

प्राइवेट चॉपर से गए विदेश

गुजरात सरकार के एक उच्चस्तरीय सूत्र के मुताबिक अस्थाना एक बार एक उद्योगपति के प्राइवेट चॉपर से विदेश गए थे। अंतिम समय में अहमदाबाद इंटरनैशनल एयरपोर्ट से यह ट्रिप वास्तव में अस्थाना के एक पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए फाइनल की गई थी।

गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान वह राज्य के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वह ढुल वडोदरा, जॉइंट CP अहमदाबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस सूरत और वडोदरा रहे। वडोदरा पुलिस चीफ के तौर पर उन्होंने अहमदाबाद में हुए 2008 सीरियल धमाकों की जांच की थी।

जून 2016 में जब CBI ने महत्वपूर्ण मामलों की जांच को तेज करने के लिए एसआईटी गठित की तो इसे लीड करने के लिए अस्थाना को कहा गया। उन्होंने राजनीतिक रूप से संवेदनशील कई मामलों की जांच की, जैसे- अगुस्टा वेस्टलैंड स्कैम, INX मीडिया केस, विजय माल्या के खिलाफ किंगफिशर एयरलाइंस लोन फ्रॉड, राजस्थान का ऐंबुलेंस स्कैम, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कार्ति चिदंबरम भी घिरे थे।

चारा घोटाले की भी जांच और लालू यादव को आरोपी भी आस्थाना के नेतृत्व वाली टीम ने ही बनाया था। विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा अब मोदी के हाथ पूरी तरह छीन गया है। अब राम जी ही मोदी की नैया पार लगा सकते हैं।

(लेखक फॉरवर्ड प्रेस मैग्ज़ीन के संपादक हैं)